IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

वित्तीय समावेशन के सन्दर्भ में आयु जनसांख्यिकीय के आधार पर ग्रामीणों की प्रधानमंत्री जनधन योजना की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन

संतोष कुमार वर्मा
शोध छात्र
वाणिज्य विभाग,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
(यू0पी0)

शोध संक्षेप

इस शोध का उद्देश्य वित्तीय समावेशन के सन्दर्भ में आयु जनसांख्यिकीय के आधार पर ग्रामीणों की प्रधानमंत्री जनधन योजना की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना है । इस अध्ययन के लिए हमने अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप के साथ वर्णनात्मक शोध अभिकल्प का प्रयोग किया गया है, जिसमें हमने सांख्यिकी उपकरण जिसमें प्रमुख रूप से आवृत्ति टेस्ट (Freqyency Test), स्वतंत्र टी–परीक्षण (Independent T-Test) का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है।है । आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण के लिए चित्र का भी इस्तेमाल किया गया है। इस शोध के लिए पांच प्रतिशत सार्थकता स्तर निर्धारित किया गया था जिससे कि हम शोध परिकल्पनाओं को स्वीकार एवं निरस्त कर सकें । इस शोध का निष्कर्ष यह है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मण्डल में वित्तीय समावेशन के सन्दर्भ में कम आयु वर्ग एवं अधिक आयु वर्ग ग्रामीणों की प्रधानमंत्री जनधन योजना की जागरूकता समान नही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में जागरूकता के संबंध में कम आयु वर्ग ग्रामीण उत्तरदाताओं की तुलना में अधिक आयु वर्ग ग्रामीण उत्तरदाता अधिक जागरूक हैं।

शब्द संकेत – वित्तीय समावेशन, प्रधानमंत्री जनधन योजना

प्रस्तावना

''वित्तीय समावेशन'' शब्द का प्रयोग इक्कीसवीं सदी में आर्थिक प्रगति की चर्चाओं में अक्सर किया जाता है। चूंकि वित्तीय प्रणाली आर्थिक विकास का समर्थन करती है, इसलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि प्रणाली में अंतिम व्यक्ति को शामिल करना महत्वपूर्ण है। नतीजतन, एक समावेशी वित्तीय प्रणाली आर्थिक विकास को काफी बढ़ा सकती है। इसके किसी अन्य घटक को संबोधित करने का प्रयास करने से पहले यह पूरी तरह से समझना महत्वपूर्ण है कि वित्तीय समावेशन में क्या शामिल है। इसके लिए, हम वित्तीय समावेशन की दो परिभाषाओं का उपयोग करते हैं जो भारत में सबसे अधिक बार उपयोग की जाती हैं, जैसा कि वित्तीय समावेशन पर रंगराजन समिति (2006) द्वारा कहा गया है। इस परिभाषा के अनुसार, ''वित्तीय समावेशन यह

सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है कि कमजोर वर्गों और निम्न–आय वाले समूहों की वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है'' और साथ ही उचित मूल्य पर समय पर और पर्याप्त ऋण जब उन्हें इसकी आवश्यकता होती है। ये परिभाषाएं अर्थव्यवस्था में सभी को वित्तीय सेवाओं तक सस्ती पहुंच प्रदान करने पर केंद्रित हैं। वित्तीय समावेशन का अर्थ अक्सर विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाओं के लिए सस्ती, सार्वभौमिक पहुंच के रूप में समझा जाता है। इनमें बैंकिंग सामान के साथ–साथ बीमा और इक्विटी उत्पादों सहित अन्य वित्तीय सेवाएं भी शामिल हैं। कम आय वाली आबादी को स्थापित बैंकिंग उद्योग की सीमाओं में लाकर, वित्तीय समावेशन दबाव की स्थितियों में उनके वित्तीय धन और अन्य संसाधनों की सुरक्षा करता है। कानूनी ऋण प्राप्त करना आसान बनाकर, यह सुविधाहीन समूहों के सूदखोर साहूकारों के दुरुपयोग को भी कम करता है। वित्तीय समावेशन भी ग्रामीण आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से के बीच बचत की संस्कृति को प्रोत्साहित करके और वित्तीय प्रणाली के संसाधन आधार का विस्तार करके आर्थिक विकास की प्रक्रिया में एक भूमिका निभाता है। मौजूदा व्यवसायों के बीच बाजार विस्तार और प्रतिद्वंद्विता को एक मजबूत वित्तीय प्रणाली द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि कम आय वाले परिवार और छोटे व्यवसाय के मालिक बिचौलियों पर निर्भर न हों। दूसरी ओर, एक खराब विकसित वित्तीय प्रणाली अप्रतिस्पर्धी, रूढ़िवादी और वंचितों या छोटे व्यवसाय के मालिकों के हितों के प्रति शत्रुतापूर्ण हो सकती है। आर्थिक विस्तार पारंपरिक रूप से वित्तीय विकास के साथ रहा है, जो दोनों के बीच संबंधों को गहरा करता है। सभी जनसांख्यिकीय समूह अब मुख्यधारा के वित्तीय क्षेत्र में अधिक से अधिक भाग लेते हैं।

साहित्य समीक्षा

साहित्य की समीक्षा शोध पद्धति का एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि यह उन प्रख्यात विद्वानों के योगदान पर प्रकाश डालता है जिन्होंने वर्तमान विषय पर अपने विचार, राय, तथ्य, सिद्धांत और दृष्टिकोण पर विचार किया है। इसके अलावा, साहित्य की समीक्षा पहले किए गए योगदान के बीच मौजूद शोध अंतराल को परिभाषित करने का प्रयास करती है। कालानुक्रमिक क्रम में प्रासंगिक साहित्य की समीक्षा नीचे दी गई है: इस शोध में, लेखकों ने ''भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में वित्तीय समावेशन की भूमिका'' पर अध्ययन किया और पाया कि अध्ययन अवधि में डेबिट कार्ड का उपयोग काफी बढ़ा और बैंकों ने ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। फिर भी, यह जानना निराशाजनक है कि देश में समावेशी बैंकिंग पहल जैसे सहकारी आंदोलन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना आदि की शुरुआत के वर्षों बाद भी, उन लोगों की संख्या जिनके पास पहुंच है बैंकिंग प्रणाली द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिए अविश्वसनीय रूप से कम बनी हुई है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वित्तीय समावेशन भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण रूप से मदद करता है और समावेशी विकास प्राप्त करने के

लिए अभी भी जगह है। **(Joseph & Varghese, 2014)**[1] सामान्यीकृत ऋण छूट पर निष्कर्ष यह है कि वे भविष्य में इस तरह की छूट की उम्मीदों का निर्माण करते हैं और किसानों को हतोत्साहित करते हैं। इसके साथ ही, ऋणदाता खराब उधारकर्ता व्यवहार की प्रत्याशा में अपने ऋण संचालन के आकार को सीमित करना पसंद करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप किसानों के लिए सुलभ ऋण में कमी आती है। नतीजतन, लेख भविष्य में सार्वभौमिक छूट का कड़ा विरोध करता है। हालांकि, लक्षित कार्रवाई जिसमें मामला–दर–मामला आधार पर छूट दी जाती है, एक उपयुक्त दृष्टिकोण हो सकता है, खासकर यदि यह तीव्र कृषि संकट को कम करने के लिए एक समग्र पैकेज का हिस्सा है। **(Hoda & Terway, 2015)**[2] इस शोध में, लेखकों ने ''भारत में वित्तीय समावेशन और विकास और गरीबी पर इसके प्रभाव'' पर अध्ययन किया और पाया कि लक्ष्य अभी भी पूरा होने से बहुत दूर है। बुनियादी शिक्षा की कमी, बाजार का सख्त नियामक वातावरण, बुनियादी ढांचे की उच्च रखरखाव लागत, और कई अन्य कारक सभी योगदान कारक हो सकते हैं। हालाँकि, यह एक ऐसा अंतराल है जिसकी जाँच की जा सकती है और यह इस अध्ययन के दायरे से बहुत बाहर है। हालांकि, सरकार को वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि राष्ट्र समावेशी विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। **(Kanhaiya & Phatak, 2017)**[3] इस शोध जांच में, लेखकों ने ''भारत में वित्तीय समावेशन'' पर अध्ययन किया और पाया कि बैंकिंग प्रौद्योगिकियों का विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है। आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) की सहायता से, जो मोबाइल बैंकिंग, ई–वॉलेट और वर्चुअल कार्ड जैसे विभिन्न समाधान प्रदान करने के लिए डिजिटल आधारभूत संरचना विकसित करता है, ग्रामीण आबादी के लिए वित्तीय समावेशन लाना आसान है। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार कई परियोजनाएं चला रहे हैं। **(Ahmad & Singhal, 2017)**[4] इस शोध जांच में, लेखक ने ''भारत में वित्तीय समावेशन और कृषि विकास'' पर अध्ययन किया और पाया कि वित्तीय संस्थानों और सामाजिक ऋण हस्तांतरण का लाभ आम तौर पर कुछ प्रमुख कृषि फार्मों द्वारा प्राप्त किया जाता है, जबकि छोटे किसान, जिनमें समाज का गरीब क्षेत्र शामिल है, को बाहर रखा गया है। इन मुद्दों को दूर करने के लिए, एक ठोस कार्य योजना और इसके उचित कार्यान्वयन की आवश्यकता है, ताकि वित्तीय समावेशन वास्तव में देश में प्रमुख कृषि विकास का मार्ग प्रशस्त कर सके और समावेशी विकास ला सके, जिससे देश की गरीबी और असमानता की स्थिति को कम किया जा सके और अंततः समाप्त किया जा सके। . अंत में, हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब प्रत्येक भारतीय के पास एक बैंक खाता होगा और वह सीधे अर्थव्यवस्था में शामिल होगा। **(Choudhury, 2018)**[5] इस शोध जांच में, लेखकों ने ''बैंकिंग उद्योग के संदर्भ

[1] Joseph, M. J., & Varghese, D. T. (2014). Role of Financial Inclusion in the Development of Indian Economy. *Journal of Economics and Sustainable Development*, *5*(11), 6–11. www.iiste.org

[2] Hoda, A., & Terway, P. (2015). Credit policy for agriculture in India - An evaluation. *Indian Council for Research on International Economic Relations*, *June*, 1–42. http://icrier.org/pdf/Working_Paper_302.pdf%0Aicrier.org/pdf/Working_Paper_302.pdf%0A%0A

[3] Kanhaiya, A., & Phatak, S. S. (2017). Financial Inclusion in India and its Impact on Development and Poverty. *Vidyasagar University Journal of Economics*, *XXII*, 29–39.

[4] Ahmad, M., & Singhal, D. R. (2017). Financial inclusion in India. *Parichay: Maharaja Surajmal Institute Journal of Applied Research Financial*, *15*(22), 11–16. https://doi.org/10.12724/ajss.53.3

[5] Choudhury, S. (2018). Financial Inclusion and Agricultural Development in India. *International Journal of Research - GRANTHAALAYAH*, *6*(9), 421–433. https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v6.i9.2018.1254

में भारत में वित्तीय समावेशन पर एक अध्ययन'' पर अध्ययन किया और पाया कि साक्षरता निवेश ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए एक आवश्यकता है, यह स्वाभाविक रूप से वित्तीय समावेशन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन प्रतीत होता है। हालांकि, ऊपर एकत्र किए गए आंकड़े बताते हैं कि साक्षरता गरीबी को कम करने में मदद कर सकती है, लेकिन यह अपने आप में उच्च स्तर के वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित नहीं कर सकती है। नीति निर्माताओं और उधारदाताओं को अध्ययन के निष्कर्षों को उपयोगी समझना चाहिए क्योंकि वे वित्तीय समावेशन के लिए अभियान को बढ़ाने के रचनात्मक तरीकों की जांच करते हैं। **(Potluri & Sulochana, 2018)**[6] इस शोध जांच में, लेखकों ने ''भारत में कृषि ऋण प्रणालीः विकास, प्रभावशीलता और नवाचार'' पर अध्ययन किया और पाया कि स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) दो ऐसे आविष्कार हैं जिन्होंने औपचारिक रूप से अंतिम मील तक औपचारिक ऋण की पहुंच बढ़ा दी है। आधिकारिक कागजात (जैसे आर्थिक सर्वेक्षण) के अनुसार, मार्च 2016 तक कुल मिलाकर 150 मिलियन केसीसी वितरित किए गए थे। इसके अलावा, बैंकिंग क्षेत्र को वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) मानकों का पालन करना चाहिए। छोटे और सीमांत किसानों की। वे निर्धारित करते हैं कि छोटे और सीमांत किसानों को समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) का कम से कम 8ः या ऑफ–बैलेंस–शीट एक्सपोजर की क्रेडिट समकक्ष राशि, जो भी अधिक हो (कृषि क्षेत्र के लिए अनिवार्य 18ः में से) प्राप्त होता है। **(Gulati & Juneja, 2019)**[7] इस शोध जांच में, लेखकों ने ''ग्रामीण भारत के वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास'' पर अध्ययन किया और पाया कि यह अध्ययन इस बात की जांच करता है कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा सचिव की आवश्यकताओं के अनुसार आरबीआई के माध्यम से वित्तीय समावेशन में बैंकिंग नियमों को अद्यतन किया। आम आदमी की वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच को सुगम बनाने के लिए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। बैंकिंग–लिंकेज कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कई पहल की जाती हैं। एक वित्तीय संस्थान के सहयोग से, भारत सरकार एक ग्रामीण उद्यमी को रियायती राशि प्रदान करती है। **(Abdullah, 2021)**[8]

अध्ययन के उद्देश्य

- उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मण्डल में वित्तीय समावेशन के सन्दर्भ में आयु जनसांख्यिकीय के आधार पर ग्रामीणों की प्रधानमंत्री जनधन योजना की जागरूकता का अध्ययन करना।

[6] Potluri, M. ambika, & Sulochana, M. N. M. (2018). A STUDY ON FINANCIAL INCLUSION IN INDIA WITH REFERENCE TO BANKING INDUSTRY. *International Journal OfManagement and Social Science Research Review*, *1*(45), 61–65. https://doi.org/10.18843/ijms/v6i4/04

[7] Gulati, A., & Juneja, R. (2019). *Agricultural Credit System in India: Evolution, Effectiveness and Innovations*. *September*.

[8] Abdullah, A. (2021). Financial Inclusion and Economic Growth of Rural India. *International Journal of Creative Research Thoughts*, *9*(2), 960–968.

शोध परीकल्पना

$H0_1$: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मण्डल में वित्तीय समावेशन के सन्दर्भ में कम आयु वर्ग एवं अधिक आयु वर्ग ग्रामीणों की प्रधानमंत्री जनधन योजना की जागरूकता समान है ।
$H1_1$: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मण्डल में वित्तीय समावेशन के सन्दर्भ में में कम आयु वर्ग एवं अधिक आयु वर्ग ग्रामीणों की प्रधानमंत्री जनधन योजना की जागरूकता समान नही है ।

अध्ययन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाले गोरखपुर मण्डल का चयन किया गया है ।

अध्ययन की इकाई

इस अध्ययन के लिए 110 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है । राष्ट्रीय युवा नीति–2014 के अनुसार 15 से 29 आयु के लोगों को युवा माना गया है। इसी को आधार मानकर प्रस्तुत अध्ययन में उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के द्वारा 15 वर्ष से 29 वर्ष की आयु के उत्तरदाताओं को कम आयु वर्ग एवं 29 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के उत्तरदाताओं को चयन किया गया है। (Singh, 2014)[9]

सैंपलिंग की तकनीक

इस अध्ययन के लिए नान प्रोबेबिलिटी कन्वीनियंस सेंपलिंग तकनीक का प्रयोग किया गया है क्योंकि यह तकनीक सुविधाजनक है एवं कम समय में यह सेंपलिंग की जा सकती है।

अनुसंधान क्रियाविधि

इस अध्ययन के लिए अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप के साथ वर्णनात्मक शोध अभिकल्प दोनों का प्रयोग किया गया है क्योंकि वर्णनात्मक शोध अभिकल्प के द्वारा नया ज्ञान, नई खोज की जा सकती है जोकि हमारे शोध की परिकल्पनाए बनाने में मदद करती हैं जबकि अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप से हम उन परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं जिसमें कई प्रकार के सांख्यिकी के उपकरण लगाए जाते हैं जो हमारे सही निर्णय लेने में सहायता करते हैं ।

आंकड़ा संग्रहण

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मण्डल में वित्तीय समावेशन के सन्दर्भ में ग्रामीण महिलाओं एवं पुरुषों की प्रधानमंत्री जनधन योजना की जागरूकता का अध्ययन करने के लिए हमने प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ा इकट्ठा किया है । प्राइमरी डाटा इकट्ठा करने के लिए हमने एक प्रश्नावली का निर्माण किया है एवं द्वितीयक आंकड़ा के लिए हमने कई प्रकार के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जनरल्स का अध्ययन किया है तथा समाचार पत्रों का भी

[9] Singh, J. (2014). National Youth Policy 2014. Ministry of Youth Affairs & Sports.

इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मण्डल में वित्तीय समावेशन के सन्दर्भ में ग्रामीण महिलाओं एवं पुरुषों की प्रधानमंत्री जनधन योजना की जागरूकता का अध्ययन की अधिक जानकारी के लिए किया गया है ।

सांख्यिकीय उपकरण

इस अध्ययन की विश्लेषण के लिए हमने कई प्रकार के सांख्यिकी उपकरण का प्रयोग किया है जिसमें प्रमुख रूप से आवृत्ति टेस्ट (Freqyency Test), स्वतंत्र टी–परीक्षण (Independent T-Test) का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है।

निर्णय नियम

इस अध्ययन के प्रारंभ में ही हमने सार्थकता स्तर 5 प्रतिशत तय कर लिया है जिसका अर्थ है की हम अपने निर्णय में 95 प्रतिशत निश्चित है एवं केवल हमसे 5 प्रतिशत की गलती शोध परिकल्पनाओ के स्वीकार और निरस्त करने में हो सकती है । यदि हमारे अध्ययन में सार्थकता वैल्यू 0.05 से कम आती है तो हम नल हाइपोथिसिस को निरस्त करेंगे एवं यदि सार्थकता वैल्यू 0.05 से अधिक आती है तो हम नल हाइपोथिसिस को स्वीकार करेंगे ।

आंकड़ा विश्लेषण

शोध परीकल्पना

$H0_2$: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मण्डल में वित्तीय समावेशन के सन्दर्भ में कम आयु वर्ग एवं अधिक आयु वर्ग ग्रामीणों की प्रधानमंत्री जनधन योजना की जागरूकता समान है।

Table 1: Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
									95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
Awareness about Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)	Equal variances assumed	.020	.887	4.416	108	.000	.960	.217	.529	1.391
	Equal variances not assumed			4.405	98.315	.000	.960	.218	.528	1.393

Source: SPSS 23.0 output

उपरोक्त तालिका संख्या 3 से यह स्पष्ट है कि सार्थकता स्तर 0.000 , 0.05 से कम है अतः नल हाइपोथेसिस $H0_1$ को अस्वीकार कर सकते हैं अतः हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मण्डल में वित्तीय समावेशन के सन्दर्भ में कम आयु वर्ग एवं अधिक आयु वर्ग ग्रामीणों की प्रधानमंत्री जनधन योजना की जागरूकता समान नही है ।

Table 2: Group Statistics

	Age of the respondents	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Awareness about Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)	Elder Age Group	63	3.49	1.120	.141
	Young Age Group	47	2.53	1.139	.166

Source: SPSS 23.0 output

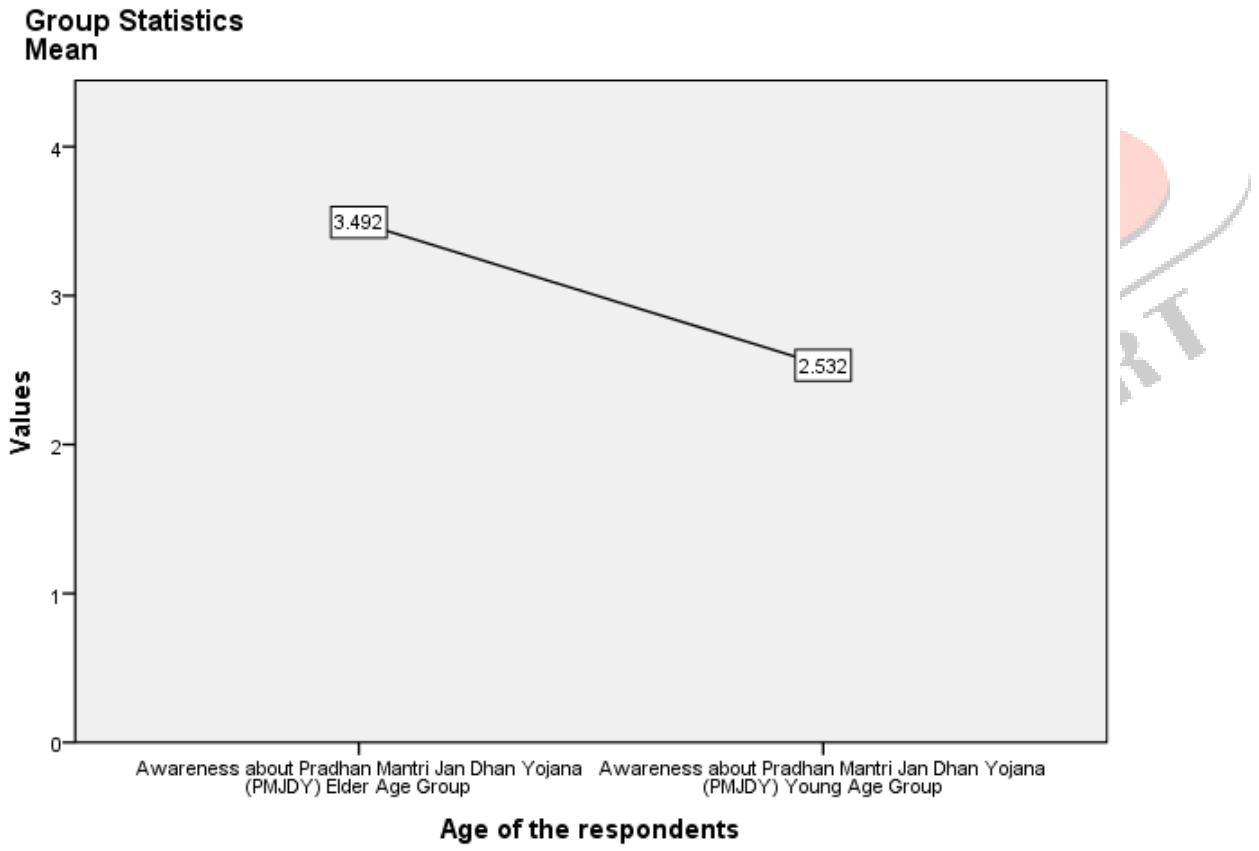

Figure 1: Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana awareness between high and low age group respondents

Source: SPSS 23.0 output

उपरोक्त तालिका संख्या 2 एवं चित्र संख्या 1 से यह स्पष्ट है कि अधिक आयु वर्ग ग्रामीण उत्तरदाताओं के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना की जागरूकता का औसत स्कोर 3.492 है जबकि कम आयु वर्ग ग्रामीण उत्तरदाताओं के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना की जागरूकता का औसत स्कोर 2.532 है, इसलिए यह

निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में जागरूकता के संबंध में कम आयु वर्ग ग्रामीण उत्तरदाताओं की तुलना में अधिक आयु वर्ग ग्रामीण उत्तरदाता अधिक जागरूक हैं।

निष्कर्ष

इस शोध का निष्कर्ष यह है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मण्डल में वित्तीय समावेशन के सन्दर्भ में कम आयु वर्ग एवं अधिक आयु वर्ग ग्रामीणों की प्रधानमंत्री जनधन योजना की जागरूकता समान नही है ।प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में जागरूकता के संबंध में कम आयु वर्ग ग्रामीण उत्तरदाताओं की तुलना में अधिक आयु वर्ग ग्रामीण उत्तरदाता अधिक जागरूक हैं।

संदर्भ सूची:

Reference

Abdullah, A. (2021). Financial Inclusion and Economic Growth of Rural India. *International Journal of Creative Research Thoughts*, *9*(2), 960–968.

Ahmad, M., & Singhal, D. R. (2017). Financial inclusion in India. *Parichay: Maharaja Surajmal Institute Journal of Applied Research Financial*, *15*(22), 11–16. https://doi.org/10.12724/ajss.53.3

Choudhury, S. (2018). Financial Inclusion and Agricultural Development in India. *International Journal of Research -GRANTHAALAYAH*, *6*(9), 421–433. https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v6.i9.2018.1254

Gulati, A., & Juneja, R. (2019). *Agricultural Credit System in India: Evolution, Effectiveness and Innovations*. *September*.

Hoda, A., & Terway, P. (2015). Credit policy for agriculture in India - An evaluation. *Indian Council for Research on International Economic Relations*, *June*, 1–42. http://icrier.org/pdf/Working_Paper_302.pdf%0Aicrier.org/pdf/Working_Paper_302.pdf%0A%0A

Joseph, M. J., & Varghese, D. T. (2014). Role of Financial Inclusion in the Development of Indian Economy. *Journal of Economics and Sustainable Development*, *5*(11), 6–11. www.iiste.org

Kanhaiya, A., & Phatak, S. S. (2017). Financial Inclusion in India and its Impact on Development and Poverty. *Vidyasagar University Journal of Economics*, *XXII*, 29–39.

Potluri, M. ambika, & Sulochana, M. N. M. (2018). A STUDY ON FINANCIAL INCLUSION IN INDIA WITH REFERENCE TO BANKING INDUSTRY. *International Journal OfManagement and Social Science Research Review*, *1*(45), 61–65. https://doi.org/10.18843/ijms/v6i4/04

Singh, J. (2014). National Youth Policy 2014. Ministry of Youth Affairs & Sports.